उर्वरक के उत्पादकों को देना चाहती है उस पर उद्योग समन्वय समिति का जो नियंत्रण है, तो इस समिति का गठन किस प्रकार होता है तथा तकनीकी व्यक्तियों का समन्वय किस तरह से होता है और सरकार का नियंत्रण उस पर किस प्रकार से होता है, जिसकी वजह से सरकार यह समझती है कि उसके दिशा-निर्देशो का पालन किया जा रहा है? चूंकि ऐसा नहीं होता है, इसी कारण से उर्वरक उत्पादकों को अनुचित सहायता लेने में आसानी होती है और वह उठाते रहते हैं और किसान इससे वंचित रह जाता है। इस संबंध में सरकार क्या प्रक्रिया अपना रही है?

SHRI EDUARDO FALEIRO: As I have mentioned earlier, nobody has attacked, not the Comptroller and Auditor-General at least, the way of functioning of the Committee as such. But, there is an observation on how the norms can be met.

SHRI JAGESH DESAI: I have carefully gone through the answers of the hon. Minister. There are two aspects. C.A.G. may also be right and the Department may also be right. It depends upon the method of accounting. If it is according to the mercantile system, then his department is right; if it is on cash basis, then the C.A.G. is right. So when the audit paragraph was given earlier, was it brought to the notice of the CAG that they were maintaining the books under the mercantile system whether they incur expenses or not they have to put in their books of account. So...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Sorry.

राजस्थान में पेयजल की कमी

*321. **श्री मूल चन्द मीणा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान से राज्य के पिछड़े जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(घ) क्या उक्त योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गई राशि पर्याप्त थी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए पिछड़े जिलों का कोई अलग से वर्गीकरण नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट समस्याओं के आधार पर "बिन पेयजल स्रोत' वाले समस्याग्रस्त गाँवों आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों/बसावटों, आदि की कवरेज के लिए सभी जिलों की योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए केन्द्रीय सहायता योजनावार आधार पर उपलब्ध नहीं

कराई जाती है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को उन योजनाओं जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गई है अथवा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा योजनाएं अनुमोदित की गई हैं, के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं। मिनी-मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को रिलीज की जाती हैं। उप-मिशनों के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार को रिलीज की जाती हैं। वर्ष 1991-92 में राजस्थान सरकार को कुल 77.13 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी।

Losses suffered by HPF

*323. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news report, appeared in the 'Business Times' section of the 'Times of India' on February 9, 1993 regarding the financial losses suffered by the Hindustan Photofilm Manufacturing Co. Ltd. (HPF) on account of accumulation of stock due to sudden opting out by some of its major stockists;

(b) if so, the amount of such losses;

(c) whether Government are aware of the serious charges of bungling in imports by HPF;

(d) whether the allegations have been examined and if so, the details thereof; and

(e) what actions are contemplated by Government to improve the viability of HPF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) The difficulties in disposing of certain items of converted products were the result of adverse market conditions and are not attributable to withdraw by major stokists. The company is endeavouring to dispose of these stocks to its best advantage.

(c) and (d) Some allegations had been received against the management of HPF regarding malpractices and mismanagement which are under verification.

(e) The steps taken by Government to improve the viability of HPF include introduction of a Voluntary Retirement Scheme, a study by the Bureau of Industrial cost and prices of the costing and pricing of its products and provision of budgetary support for completion of the Polyester-based X-Ray project.

Multi-storeyed hi-tech industrial complex

*326. DR. ISHWAR CHANDRA GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Rs. 100 crore multi-storeyed hi-tech industrial complex in Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to form a corporation for setting up such industrial complex in rural areas of the country, especially in U.P., for the weaker section of the society;

(d) if so, the details trereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE